ISSN:2349-7858

Available online at http://www.sajms.co.in/index.php/sajms

South Asia Journal of Multidisciplinary Studies SAJMS December 2020, Vol. 6, No 11

उत्तर कोरिया– दक्षिण कोरिया विवाद की पड़ताल पीत सागर की पृष्ठभूमि में

निखिल कुमार सिह

Associate Professor, Department of Defense and Strategic Studies

साराशं

कोरिया पूर्वी एशिया का एक प्रायद्वीप है जो मंचूरिया की दक्षिण–पूर्व सीमा से लगता हुआ यलो सी तक विस्तृत है तथा जापान के मुख्य द्वीपो के धुर दक्षिण भाग तक पहुचता है यह प्रायद्वीप वर्षों तक जापान के कब्जे में रहां।

वर्ष 1910 में कोरिया का विभाजन नहीं हुआ था, उस पर जापानी हुकूमत थीं दूसरे विश्वयुद्ध में जापान हार गया लेकिन कोरिया पर उसकी पकड़ बनी रहीं कोरिया को आजाद कराने के उद्देश्य से अमेरिका और सोवियत संघ ने हाथ मिलाया और जापानी सेना से उसे मुक्ति दिलाईं जापानी हुकूमत खत्म हो जाने के बाद कोरिया दो भागों क्रमंशः उत्तरी कोरिया और दक्षिण कारिया में विभक्त हो गयां कोरिया का उत्तरी हिस्सा सोवियत संघ के कब्जे में चला गया जबकि दक्षिणीा हिस्सा अमेरिकी कब्जे में आ गयां अमेरिका और सोवियत संघ (विशेषकर सोवियत संघ) की यह प्रबल इच्छा थी कि कोरिया का दो भागों में विभाजन कदापि उचित नहीं है, बेहतर यह होगा कि यहां एक ही सर्वमान्य सरकार का गठन हों दुर्भाग्य से सोवियत संघ की यह सद्इच्छा पूरी नहीं हो सकीं कोरिया में वर्ष 1948 में उत्तर कोरिया में अलग सरकार बनी और दक्षिण कोरिया में अलगं उत्तर कोरिया में जो सरकार बनी उसका नेतृत्व कोरियाई कम्युनिस्ट कर रहे थे, जबकि दक्षिणी कोरिया में सिंगमन री के नेतृत्व में अनेक राजनीतिक दलों को साथ लेकर कोरियाई गणराज्य की सरकार बनीं सिंगमन री को कम्युनिस्टों से धृणा थी और उसकी यह प्रबल इच्छा थी कि किसी भी तरह से कम्युनिज्म को बढने से रोका जाना चाहिएं री की इसी इच्छा के चलते उसके उत्तरी कोरिया से बेहतर संबंध नहीं बन पाए और दोनों के बीच झड़पे शुरू हो गईं अमेरिका गुपचुप तरीके से री को उत्तर कोरिया के खिलाफ भडकाता रहां परिणामतः जून, 1950 में उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों के बीच भीषण युद्ध हो गयां इसी बीच चूकि चीन में जनवादी क्रांति हो चुकी थी और अमेरिका को इस बात का डर बेवजह सता रहा था कि कहीं इस पूरे क्षेत्र को कम्युनिज्म अपने चपेट में न लेले जिससे भविष्य में उसकी जो योजनाएं इस क्षेत्र में अपना प्रभाव जामने के लिए बनाई गई है, वे अवरूद्व हों ऐसे में अमेरिका ने अपना असली चरित्र उजागर किया और अपनी फौंजे दक्षिणी कोरिया की मदद के लिए भेज दीं दिखावे के लिए अमेरिकी फौजों के साथ उसके कुछ अन्य मित्रों की फौंजों का भी घालमेंल कर दिया गया लेकिन मुख्य फौजी ताकत अमेरिका की ही थीं अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में भी अपना प्रभाव तो ब ना ही लिया था लिहाता उत्तरी कोरिया के रवैये की निंदा भी उसने संयुक्त राष्ट्र से करवा ही लीं दुनिया को बेवकूफ मानते हुए अमेरिका ने कुछ इस तरह का नाटक रचाा जिससे यह लगे कि यह हमला संयुक्त राष्ट्र की सनाऐंल ड़ रही हैं अमेरिका के इस नाटक के चलते तीसरे विश्वयुद्ध का खतरा भी मंडराने लगा था क्योकि इससे चीन भी नाराज होकर सक्रिय हो चुका थां और सोवियत संघ भी जो एक सशक्त फौजी ताकत बन चुका था, वह भी कुपित हो उठां फिर भी सोवयित संघ ने बराबर यही कोशिश की कि यह युद्ध किसी भी रूप में उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया की सरहद के बाहर तक न फैल पाए अन्यथा तीसरे विश्वयुद्ध को होने से कोई नहीं रोक सकता हैं तीन सालों तक यह दोनों देश लड़ते रहे और इसमें लाखों नागरिक और सैनिकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा मारे गए लोगों में डेढ़ लाख के आस–पास अमेरिकी भी थें अपार धन और जनहानि के बाद अंततः वर्ष 1953 में दोनों मुल्कों के बीच संधि हुई और युद्ध रूकां।

प्रस्तावनाः–1953 के युद्ध स्थगन के पश्चात उनके मध्य की सामुद्रिक सीमा का निर्धारण नहीं हो सका थां अमेरिकी नेतृत्व वाली संयुक्त राष्ट्र सेना द्वारा दोनों के बीच सामुद्रिक धुसपैठ को रोकने के लिए पीत सागर में समुद्री सीमांकन रेखा उत्तरी सीमा रेखा की एकरतफा घोषणा की गई थी जिसे उत्तर कोरिया मान्यता नहीं देता है दोनों देशों के बीच सामुद्रिक सीमा के संदर्भ में कई गंभीर झड़पे हो चुकी हैं तथा हाल ही में नवंबर, 2009 में दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच हुई गोलीबारी तथा दिसंबर 2009 में उत्तर कोरिया द्वारा पीले सागर में विवादित सीमा के साथ–साथ 'शांतिकालीन फायरिंग क्षेत्र ' की स्थापना के साथ वह विवाद पुनः गहराता दिख रहा हैं

इस विवाद का मूल कारण 1948 में दोनों राष्ट्रों उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के रूप में सम्पूर्ण प्रायद्वीप के विभाजन में हैं

1948 में दोनों देश सम्प्रभु राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आ गये किन्तु इनके संविधान में आज भी पृथवकरण को स्वीकृति नहीं प्रदान की गई हैं उत्तर कोरिया के संविधान की धारा 1 में उल्लिखित है कि लोकतांत्रिक जनतांत्रिक गणराज्य कोरिया एक स्वतंत्र समाजवादी राष्ट्र है जो समस्त कोरियाई लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है तथा इसी प्रकार दक्षिण कोरिया के संविधान की धारा 3 के अनुसार कोरिया गणराज्य के क्षेत्र में सम्पूर्ण कोरिया प्रायद्वीप शामिल हैं महाशक्तियों द्वारा विभाजन से असहमत दोनों कोरिया 1950 में युद्धरत हो गयें 4 वर्ष पश्चात 1953 में युद्ध स्थगन रेखा पर दोनों देशों के मध्य विसैन्यीकृत क्षेत्र बनाया गया हैं वर्तमान में यही दोनों कोरिया के मध्य सीमा रेखा है और यही विश्व की सर्वाधिक सैनिक जमाय वाली रेखा भी हैं चूंकि सीमा क्षेत्र निर्धारण हेतु दोनों दृष्टि से आज भी ये युद्धरत पक्ष हैं

- 21 दिसंबर, 2009 को उत्तर कोरिया द्वारा पीत सागर में विवादित उत्तरी सीमा रेखा के साथ–साथ 'शांतिकालीन' फायरिंग क्षेत्रों की स्थापना की घोषणा की गईं
- उत्तर कोरिया के अनुसार उसकी नौसेना इस क्षेत्र में कभी भी गोलीबारी प्रारंभ कर सकती हैं अतः इस क्षेत्र में आने वाली सभी मत्स्य–ग्रहण नौकाओं और रणपोतों को अपनी सुरक्षा मानदण्ड अपनाने होंगें
- उत्तर कोरिया के अनुसार यह कदम उसने दक्षिण कोरिया की नौसेना द्वारा बार–बार उसके समुद्री क्षेत्र में घुसपैठ के फलस्वरूप उठाया हैं
- मध्य दिसंबर, 2009 में उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर अपनी समुद्री सीमा के निकट समुद्र के भीतर विस्फोटको के परीक्षण का आरोप लगाया थां

- इससे पूर्व नवंबर 2009 को दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच हुई परस्पर गोलीबारी में उत्तर कोरिया की एक गश्ती नौका जल गई थी तथा एक व्यक्ति मारा गया थां
- ज्ञातत्व है कि इससे पहले 1999 और 2002 में भी दोनों कोरियाई देशों के बीच सामुद्रिक सीमा को लेकर झडपें हुई थी जिसमें दोनों से दर्जनों लोग हताहत हुए थें
- 27 मई, 2009 को अपने दूसरे परमाणु परीक्षण के बाद उत्तर कोरिया ने एनएलएल को जबरन लागू करने के प्रयासों का तत्काल सैनिक प्रत्युत्तर देने की चेतावनी दी थीं
- वस्तुतः उत्तर कोरिया सामुद्रिक सीमाकंन रेखा को दक्षिण की ओर बढ़ाना चाहता है ताकि कुछ प्रमुख द्वीप (जो वर्तमान में दक्षिण कोरिया की सीमा में है) उसकी सीमा में आ सकें
- उल्लेखनीय है कि उत्तर कोरिया अमेरिका से 1950–53 के युद्ध की समाप्ति संबंधी आपचारिक श्शांति संधि करना चाहता है तथापि अमेरिका चाहता है कि पहले उत्तर कोरिया छः पक्षीय नाभिकीय निःशस्त्रीकरण वार्ता में पुनः शामिल हों

उत्तरी कोरिया से अमेरिकी रिश्ते आज भी ठीक नहीं हैं अमेरिका ने कोरिया को भी श्शैतान राष्ट्रों की अपनी सूची में शामिल कर रखा हैं उत्तरी कोरिया के सिर पर चूंकि रूस और चीन का हाथ है लिहाजा अमेरिका दक्षिण कोरिया के साथ खड़ा हुआ हैं अमेरिका ने दक्षिण कोरिया और जापान में अपने सैनिक अड्डे बना रखे हैं ऐसी स्थिति में रूस और चीन उत्तर कोरिया को हर तरह की मदद देते हैं अमेरिका जब भी उत्तर कोरिया के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई करने की कोशिश करता है रूस और चीन दोनों की उसकी ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं उत्तर कोरिया ने भी कभी अमेरिका धमकी की परवाह नहीं की और अपनी सैन्रू ताकत के विस्तार मे बराबर लगा रहां इराक पर हमले से पूर्व अमेरिकी रक्षा सचिव डोनाल्ड रम्सफील्ड ने यह घोषणा जरूर की थी कि यदि आवश्यकता पड़ी तो अमेरिका, इराक और उत्तर कोरिया दोनों से एक साथ युद्ध करेगा लेकिन इस धमकी के जवाब में उत्तर कोरिया ने अमेरिका को ही धमकाने की कोशिश कीं उत्तर कोरिया यह जानता है कि उस पर किसी तरह का आर्थिक प्रतिबंध और सशस्त्र आक्रमण को भारी पड सकता हैं क्योंकि यह रूस और चीन को कभी भी स्वीकार नहीं होगां इससे उल्ट इराक पर हमला इसलिए अमेरिका के लिए आसान रहा क्योंकि उसके पडोसी मुस्लिम राष्ट्र उससे पहल` से ही नाराज थें इसके साथ ही एक दशक से कडे आर्थिक प्रतिबंध झेलने के कारण इराक की कमर करीब–करीब टूट चुकी थीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इराक अलग–थलग हो चुका थां ऐसी स्थितियां फिलहाल उत्तर कोरिया के साथ कदापि नहीं हैं यही नहीं, सबसे करारा झटका अमेरिका को तब लगा जब दक्षिण कोरिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने भी उत्तर कोरिया को शत्रु राष्ट्र घोषित करने से इन्कार कर दियां चीन के उत्तर कोरिया के साथ कई हित जुड़े हुए हैं पहला हित तो यही है कि चीन यह कदापि नहीं चाहता कि अमेरिका जैसे राष्ट्र की सेनाएं उसकी सीमाओं से आकर सट जाएं उत्तर कोरिया अभावग्रस्त है उसकी आबादी रोजगार के लिए चीन की ओर निरंतर जाती रही हैं उत्तर कोरिया से सटे हुए जो चीनी सीमांत प्रदेश है वहां बड़ी आबादी कोरियाइयों की हैं यह कोरियाई चीनी आबादी से ऐसे धुल–मिल गए हैं कि उन्हें अवैध अप्रवासी के रूप में आसानी ने नहीं पहचाना जा सकता हैं चीन यह अच्छी तरह से जानता है कि यदि उत्तर कोरिया पर अमेरिकी हमला होता है तो वहां राजनीतिक अस्थिरता के कारण उसके सीमांत प्रदेश में शरणार्थियों का सैलाब उमड़ेगाजो उसके हितों में नहीं हैं भारत के लिए जो महत्व चीन के संदर्भ में तिब्बत का है वैसा ही महत्व चीन के लिए उत्तर कोरिया का हैं हिन्दुस्तान ने तो चीनी सेनाओं को तिब्बत सौंपकर एक बड़ी भूल कर दी लेकिन चीन इस तरह की भूल कभी नहीं करेगां कुछ मिलाकर जैसा भू–राजनीतिक महत्व चीन के लिए उत्तर कोरिया का है वैसा ही स्थितियां रूस के लिए भी हैं

- विश्लेषकों के अनुसार उत्तर कोरिया एनएलएल पर विवाद को बढाकर उमेरिका पर शांति संधि के लिए दबाव बना रहा हैं
- ज्ञातव्य है कि मई 2009 में उत्तर कोरिया द्वारा परमाणु परीक्षण किए जाने के बाद संयुक्त राष्ट्र ने उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध कड़े कर दिए थें

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 12 जून को उत्तर कोरिया पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाते हुए पहले से लगे प्रतिबेंधों को दायरा और व्यापक कर दियां सुरक्षा परिषद ने यह कदम उत्तर कोरिया को हाल ही में किए गए परमाणु परीक्षण के लिए दंडित करने और उस पर निरस्त्रीकरण की वार्ता तक दुबारा आाने के लिए दबाव डलाने के उद्देश्य से उठायां आमान्य रूप से 12 जून को सुरक्षा परिषद में पारित हुआ प्रस्ताव न केवल सुनने में ज्यादा कठोर था, बल्कि यह एकमत से भी पारित हुआं यहां तक चीन ने भी सबके सामने उत्तर कारियाके ताजा कदम की आलोचना की, उसके परमाणु हथियारों की अंधदौड़ से बाहर निकालने के प्रयास में लगे देशों के बीच मतभेद अभी भी कायम हैं इन मतभेदों और इस बात की बढती अनिश्चितता ने कि कोरिया शासन वास्तव में चाहता क्या है, निकट भविष्य करने के काम को कठिन बना दिया हैं

उत्तर कोरिया पर लगाए गए नए प्रतिबंध कागजों पर तो काफी कठोर नजर आते हैं इनमें उत्तर कोरियाई हथियारों के निर्यात पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया हैं और हथियार आयात पर कड़ा नियंत्रण रखा गया हैं इसका उद्देश्य नाभिकीय और बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक के प्रसार को रोकना हैं यह प्रसार ही असल में कोरियाई शासन की नगद आमदनी का एक बड़ा व मुख्य जरिया हैं अतिरिक्त रूप से उठाए गए कदम अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय तंत्र एक उत्तर कोरिया की पहुंच को कम करेंगें इन प्रतिबंधों पर उत्तर कोरिया ने उसी भाषा में धमकी देकर प्रतिक्रिया जताई जिसकी उम्मीद सबको पहले से ही थीं कोरियाई शासन ने धमकी दी कि इसके जहाजों का यदि निरीक्षण किया गया तो वह इसका कड़ा जवाब देगां इसने प्लूटोनियम आधारित और बमों को बनाने और यूरेनियम संवर्द्धन कार्यक्रम को आगे बढाने की घोषणा कीं विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि उत्तर कोरिया आने वाले दिनों में लंबी दूरी की मिसाइल और परमाणु तकनीक के और भी परीक्षण कर सकता हैं उत्तर कोरिया अपने नौसैनिक पोतो को दक्षिण कोरिया के साथ लगी विवादित समुद्री सीमा मे भेजकर नौसैनिक झडप को भी शुरू कर सकता हैं इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल है कि नए प्रतिबंध किसी तरीके से उत्तर कोरिया को समझौता वार्ता तक फिर से आने के लिए मजबूर कर सकेंगें कुछेक अपवादों को अगर छोड दे, तो इससे पूर्व में लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों का उत्तर कोरिया पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा हैं ताजा मामले मे ंसुरक्षा परिषद में प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रस्ताव एकमत से जरूर पारित हो गया लेकिन इसके बदले में प्रस्ताव से वह प्रावधान हटाना पड़ा जिसके तहत अन्य देशों को भी उत्तर कोरियाई जहाजों की तलाशी लेने के लिए कहा गया थां अंमित रूप से जिस प्रावधान पर सहमति बनी–कि उत्तर कोरियाई जहाजों को निरीक्षण से गुजरना पडेगा लेकिन इसके लिए उन्हें मजबूर नही किया जाएगा– वह प्रतिबंध के प्रभावशाली क्रियान्वयन के लिए मुश्किल से ही कोई आशा जगता है जैसे पूर्व में हुआ इस बार भी चीन, और किसी हद तक रूस, ने उत्तर कोरिया को संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय आलोचना का संदेश देने के लिए प्रतिबंधों का समर्थन भले ही कर दि या लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वालां मुश्किल से कठोर दिखाई पड़ने वाले प्रतिबंध के प्रावधानों और सुरक्षा परिषद में पारित उस गैर प्रभावी प्रस्ताव से शायद ही कोई परिणाम निकलेगां जिसमें कहा गया है कि यह अपने पड़ोसियों से हासिल होने वाली छूट का उच्चतम स्तर हासिल

कर चुका हैं इससे भी आगे, यदि मान भी ले, कि नई प्रतिबंध जोर देकर लागू कर दिए जाएंगे तो भी यह स्पष्ट नहीं है कि उत्तर कोरिया पर आर्थिक व राजनीतिक दबाव डालने के लिए लागू ये प्रतिबंध किसी तरीके से उसके व्यवहार को बदल पाएंगें उत्तर कोरिया पहले ही दुनिया के सबसे अलग–थलग और गरीब देश में से एक हैं

उत्तर कोरिया समस्या का दीर्घकालीन हल निकालने के लिए एक संयुक्त प्रयास और सामूहिक रूप से लागू किए गए प्रतिबंधों के अलावा और चीजें भी आवश्यक हैं इस मुददे की प्रमुख समस्या केवल उत्तर कोरिया का गैर जिम्मेदाराना रवैया ही नहीं है, बल्कि इस मुददे से जुड़े दूसरे देशों के हितों में विभिन्नता भी इसकी एक बड़ी दिक्कत हैं इस समस्या से जुडे चीन, रूस, दक्षिण कोरिया, जापान व अमेरिका का इस समस्या का मूल्यांकन करने का तरीका और इसका अनके अनुकूल हल निकलने का दृष्टिकोण भी इसके हल में बहुत ज्यादा मायने रखता हैं

हालांकि उत्तर कोरिया पर चीन के प्रभाव को प्रायः जरूरत से ज्यादा करके देखा जाता है, फिर भी चीन अकेला ही आर्थिक रूप से इस लाभी कि स्थिति में ही कि वह उत्तर कोरिया को समझौता वार्ता तक लाने के लिए मजबूर कर सकता हैं दरअसल, उत्तर कोरिया अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए काफी हद तक चीन निर्भर हैं लेकिन चीन के साथ यह दुविधा है कि जिद्दी कोरियाई शासन को वार्ता के लिए राजी करने हेतु डाले गए दबाव की मात्रा और इसके समाप्त हो जाने के दबाव की मात्रा में बहुत ज्यादा अंतर नहीं हैं यदि कोरियाई शासन का अंत हुआ तो निश्चय ही इस क्षेत्र में एक मानवीय संकट शुरू हो जाएगा और इसका सबसे ज्यादा असर चीन पर ही पड़ेगा जो पहले ही उत्तर कोरिया से लगे अपने इलाकों में यह दिक्कत झेल रहा हैं चीन के लिए और रूस के लिए भी उत्तर कोरिया में कम्युनिस्ट शासन की समाप्ति का रणनीतिक हार भी साबित होगीं उत्तर कोरिया एक बफर स्टेट के रूप में रणनीतिक रूप से चीन के लिए काफी लाभदायक हैं इसके ना रहने पर कोरियाई प्रायद्वीप पर अमेरिकी सहयोग वाली ताकतों को एकछत्र राज हो जाएगां

इसके उलट, जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका के लिए परमाणु हथियार संपन्न उत्तर कोरिया स्पष्ट रूप से एक खतरा हैं लेकिन, इनमें से कोई भी देश अभी कम्युनिस्ट शासन को सत्ता से बेदखल करने के प्रयास में नहीं लगा हैं क्योंकि वह स्थिति भी हानिकारक सिद्ध होगी, खासतौर पर दक्षिण कोरिया के लिएं हांलांकि, यदि किम वंश के स्थान पर कोई आज्ञाकारी सरकार उत्तर कोरिया में बन जाती है जिसकी संभावना कम ही है, तो इन देशों को निराशा कतई नहीं होगीं

उत्तर कोरियार के खिलाफ सैन्य हस्तक्षेप फिलहाल न तो संभव है और न ही उचितं चीन का वरदहस्त प्राप्त होने के कारण उत्तर कोरिया पर प्रतिबंधों से कुछ खास असर नहीं पड़तां ऐसे में अमेरिका के पास कोरिया के परमाणु परीक्षणों और मिसाइलों की काट सिर्फ कूटनीति हैं परंतु उसके लिए आवश्यक है कि वह 6 देशों की वार्ता में उत्तर कोरिया को इस बात के लिए राजी करें कि वह अपनी नाभिकीय और मिसाइल क्षमता को सीमित करते हुए इसका दुरूपयोग न करें निःसंदेह यह अशिष्टता और धमकी के बल पर किया गया समझौता लग सकता है, लेकिन इसके सिवा अमेरिका के पास और कोई चारा नहीं हैं

- प्रतिबंधों के बाद भी उत्तर कोरिया द्वारा 2009 में प्रक्षेपास्त्र परीक्षण जारी रखे गए थें
- उत्तर कोरिया के आक्रमण रूख के बाद भी दक्षिण कोरिया पारस्परिक संबंधों को सुधारने की दुष्टि से मानवीय आधार पर उत्तर कोरिया को मदद प्रदान कर रहा हैं
- दिसंबर 2009 में ही दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया को 15 मिलियन डालर की स्वाइन फ्लू दवाएं भेजी है जो कि दक्षिण कोरिया को पिछले लगभग दो वर्षों में पहली सीधी सहायता हैं
- दिसंबर 2009 में ही दक्षिण कोरिया ने कहा है कि वह उत्तर कोरिया के नवजात शिशुओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम हेतु संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों को नकद सहयात पुनः प्रारंभ करने पर विचार कर रहा है जो कि उसने उत्तर कोरिया के मई, 2009 के परमाणु परीक्षण के बाद रोक दी थीं

सदंर्भ–

1. समसायिकी महासागर – अगस्त – 2009, पृ0 48
2. Palmer and perkins, International Relations, 1957, P, 277.
3. सिंह, पवन कुमार, – दहशतगर्द अमेरिका, अनामिका पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स (प्रा0 लि0) 469/3, 21ए अंसारी रोड, दरियांगज, नई दिल्लीं 2005,पृ0 63 –64
4. सम–सामयिक घटन चक्र– फरवरी 2010, पृ0 24
5. सिंह पवन कुमार, – दहशतगर्द अमेरिका, अनामिका पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स (प्रा0 लि0) 469/3, 21ए अंसारी रोड, दरियांगज, नई दिल्लीं 2005,पृ0 64 –65
6. सम–सामयिक घटन चक्र– फरवरी 2010, पृ0 25
7. फड़िया, डॉ0 बी0 एल0,– अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति सिद्धान्त एवं समकालीन राजनीतिक मुद्दे, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, 2009, पृ0– 108
8. सम–सामयिक घटन चक्र– फरवरी 2010, पृ0 25